

प्रेषक,
किशन नाथ,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
श्रम आयुक्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी,
नैनीताल।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग

देहरादून, दिनांक 29, मार्च, 2011

विषय-श्रम न्यायालय काशीपुर के कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रथम चरण के रूप में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-172/नजा०/एक-7/09-10, दिनांक 24 जनवरी, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010-12 में श्रम न्यायालय काशीपुर के कार्यालय भवन-निर्माण हेतु प्रथम चरण के रूप में प्रेषित किये गये आगणन रु० 5.66 लाख के सापेक्ष टी०ए०सी० वित्त द्वारा स्वीकृत/संस्तुत लागत रु० 2.36 लाख (दो लाख छत्तीस हजार मात्र) की संलग्न विवरणानुसार प्रथम किस्त के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मित्तव्ययता नितांत आवश्यक है, मित्तव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3- कार्य करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्येज रूल्स एवं मित्तव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2011 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाय।

क्रमशः पेज 2 पर....

5- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु अनुदान संख्या-16 मुख्य लेखाशीर्षक 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 80-सामान्य, आयोजनागत-001-निर्देशन तथा प्रशासन, 03-श्रम आयुक्त के अधीन आवासीय/अनावासीय भवन/भूमि क्रय की मानक मद संख्या 24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू०ओ०- 233P/XXVII(5)/2011, दिनांक 29 मार्च, 2011 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(किशन नाथ)

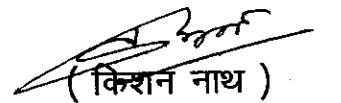
अपर सचिव।

संख्या-150 (1)/VIII/11-13(श्रम)/2010, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 3- पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, काशीपुर।
- 4- जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
- 6- परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लि०, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
- 7- निजी सचिव, मा० श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड।
- 8- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 11- एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(किशन नाथ)

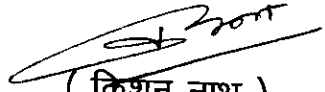
अपर सचिव।

✓

शासनादेश संख्या- 158 / VIII / 11-13(श्रम) / 2010, दिनांक 29 मार्च 2011 का संलग्नक

कार्य का विवरण	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत वर्ष 2010-11 (प्रथम चरण)	अवमुक्त की गयी कुल धनराशि	(धनराशि ' लाख में) वर्ष 2010-11 में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
श्रम न्यायालय, काशीपुर के कार्यालय भवन-निर्माण हेतु	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर।	2.36	—	2.36
योग :-		2.36	—	2.36

(धनराशि रुपये दो लाख छत्तीस हजार मात्र)


(किशन नाथ)
अपर सचिव।
६